भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2549

मंगलवार 10 अगस्त, 2021 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान और विकास में अपर्याप्त घरेलू निवेश

2549. श्री संजय सिंह:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान और विकास में घरेलू निवेश अपर्याप्त है और अर्थव्यवस्था के विकास को बनाए रखने के लिए देश में सुप्रशिक्षित वैज्ञानिकों और अभियंताओं की निरंतर कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की 'साइंस रिपोर्ट' नामक रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह बताया गया है कि देश में अनुसंधान की तीव्रता गतिहीन है और घरेलू निगमों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और व्यक्तियों द्वारा पेटेंटिंग कम है; और

(घ) यदि हां, तो कम निवेश किए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) और (ख): जी नहीं, अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय के संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास में निवेश वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के जीईआरडी में कुल 3 गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, भारत में प्रति मिलियन जनता पर पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ते हुए रूझान का अनुसरण कर रही है । नवीनतम आरएंडडी आंकड़ों के अनुसार, प्रति मिलियन जनता पर एफटीई शोधकर्ताओं की संख्या 2000 में 110 और 2015 में 218 से बढ़कर 2017 में 255 हो गई है।

(ग) और (घ): जी हां, सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसंधान तीव्रता को अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों से लगभग 07 प्रतिशत आंका गया है। जीईआरडी के सकल घरेलू उत्पाद में वांछित स्तर तक वृद्धि नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि जीईआरडी में निजी क्षेत्र का निवेश अपर्याप्त है । अन्य विकसित देशों के विपरीत जहां जीईआरडी में 70% से अधिक योगदान निजी क्षेत्र से आता है, भारत में जीईआरडी में निजी क्षेत्र का योगदान 40% से कम है। सरकार विभिन्न प्रोत्साहन पहलों के माध्यम से जीईआरडी में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है ।

*****